आज हम फल सब्जियों, गेंहू, दूध, घी सबमें जहर खा रहे हैं : हरीश चौधरी

विधानसभा में कांग्रेस विधायक हरीश चौधरी ने स्वास्थ्य विभाग की मांगों पर बहस में भाग लिया

जयपुर। कांग्रेस विधायक हरीश चौधरी ने बहस में हिस्सा लेते हुए कहा कि पीने के पानी की गुणवत्ता पर मेडिकल विभाग को रिपोर्ट स्पष्ट करनी चाहिए। पानी मे फ्लोराइड जैसे तत्व सबसे ज्यादा हैं। सरकार को इसमें सम्बंधित विभागों की जिम्मेदारी तय करनी चाहिए। थार के अंदर पानी के टांके बने हुए हैं, उनमें पानी की गुणवत्ता है। आज हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे। आज प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। मिलावटी खाने के बारे में जनता को सही जानकारी देने की हमारी जिम्मेदारी है। आज हम फल सब्जियों, गेंहू, दूध, घी सबमें जहर खा रहे हैं। सदन कोई कानून नियम नहीं बना रही।

> 'जहर मिलाने वालों के लिए हमने बड़े कमजोर नियम बना रखे हैं, ऊपर से दोषियों को बचा रहे हैं'

उन्होंने कहा कि गौमाता की जय तो बोलते हैं, लेकिन यह नहीं देख रहे की बाजार में मिल रहे गाय के घी में कितनी मिलावट आ रही है। गाय के आहार में मिल रहे पेस्टिसाइड्स से हमें दूध में जहर मिल रहा है। हरीश चौधरी ने कहा कि जहर मिलाने वालों के लिए हमने बड़े कमजोर नियम बना रखे हैं, ऊपर से दोषियों को बचा रहे हैं। हमें जांच लैब की कमी पर बात करनी चाहिए। एसएमएस अस्पताल में 15 हजार की ओपीडी होना चिंताजनक है। इलाज का विकेंद्रीकरण करना होगा। हमें किसी देश के मॉडल अपनाने की जगह राजस्थान की परिस्थितियों के हिसाब से मॉडल बनाना चाहिए। मेडिकल सेंट्रलाइज्ड करने से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को जयपुर आना पड़ता है और शहरी लोगों को निजी अस्पतालों में जाना पड़ता है। कोरोना से मेडिकल अधिकारियों ने नहीं नर्सिंग स्टाफ ने लड़ाई लड़ी। उन्हें सल्यूट करता हूं। आज उन्हीं लोगों की भर्ती नहीं हो रही। बायतु उपजिला अस्पताल के अंदर 38 स्वीकृत पदों में सिर्फ 14 पद भरे हैं। जेनरेटिक दवाइयों को बढ़ावा देने की साथ एंटीबायोटिक दवाइयों के दुष्परिणाम के बारे में भी हमें सोचना चाहिए। स्टेरॉइड के कारण बहुत मौतें हुई। हमें कोई नीति बनानी पड़ेगी। चिरंजीवी योजना के माध्यम से लोगों को 25 लाख का इलाज मिल रहा था। आज नाम बदल दिया, लेकिन लोगों को सुविधाएं नहीं मिल पा रही। इंश्योरेंस कंपनी की वजह से पैसा अटकने के कारण लोग अस्पतालों में क्लेम के लिए धक्के खा रहे हैं। सरकार को क्लेम दिलाने को प्राथमिकता नहीं है। आरजीएचएस के भुगतान के लिए मेडिकल स्टोर वाले कहते हैं कि इसका पैसा टाइम पर नहीं मिलता। टोटल फर्टिलिटी रेट को भी समझने की आज जरूरत है।

आपकी कृपा से विधायक नहीं हूं : कुलदीप धनकड़

जयपुर। विधानसभा में अनुदान मांगों पर बोलने वालों की लिस्ट से नाम काटे जाने के मुद्दे को लेकर भाजपा विधायक कुलदीप धनखड़ और सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग के बीच जमकर नोक-झोंक हुई। दोपहर में लंच टेबल पर दोनों ने एक-दूसरे को जमकर खरी-खोटी सुनाई। इस दौरान कई विधायक भी मौजूद थे, सीनियर नेताओं ने बीच-बचाव कर मामला शांत करवाया। धनखड़ स्वास्थ्य की अनुदान मांगों पर बोलना चाहते थे, लेकिन सचेतक ने उनका नाम नहीं लिखा, इस मुद्दे पर बात इतनी बढ़ी कि कई विधायकों की मौजूदगी में लंच के दौरान भिड़ गए।

> मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग और भाजपा विधायक धनकड़ के बीच हुई नोक-झोंक

धनखड़ ने गर्ग से नाराजगी जताते हुए कहा कि टारगेट बनाकर मेरा नाम हटाया गया। इस पर गर्ग ने और भी 10 विधायकों के नाम हटाने का तर्क दिया। इस बीच दोनों के बीच बहस बढ़ गई, गर्ग ने गुस्से में यहां तक कह दिया कि अपने दिमाग से गंदगी को निकाल दो। बदले में धनखड़ ने भी कह दिया को गंदगी आपके दिमाग में है। गर्ग इस पर गुस्सा हो गए, और कहा कि आपने तो मुख्यमंत्री तक शिकायत कर दी, लेकिन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाए।

धनखड़ ने फिर पलटवार किया और कहा कि मैं आपकी कृपा से विधायक नहीं हूं। इस बीच वरिष्ठ विधायकों ने बीच-बचाव किया और दोनों को शांत करवाया।

'गौशालाओं को देय अनुदान राशि में हो रही निरंतर वृद्धि'

जयपुर। गोपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने गुरुवार को विधानसभा में राज्य सरकार को गौशालाओं के रख-रखाव के लिए संवेदनशील बताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में बजट वर्ष 2024-25 में गौशालाओं को देय अनुदान सहायता राशि में दस प्रतिशत की वृद्धि की गई थी और अब बजट वर्ष 2025-26 में भी 15 प्रतिशत की वृद्धि के लिए घोषणा की गई है। कुमावत प्रश्नकाल में पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे।

उन्होंने कहा कि वर्तमान में प्रदेश में 4 हजार 140 गौशालाएं संचालित हैं। इनमें से 3 हजार 43 गौशालाएं इस वर्ष अनुदान सहायता राशि के लिए पात्र है।

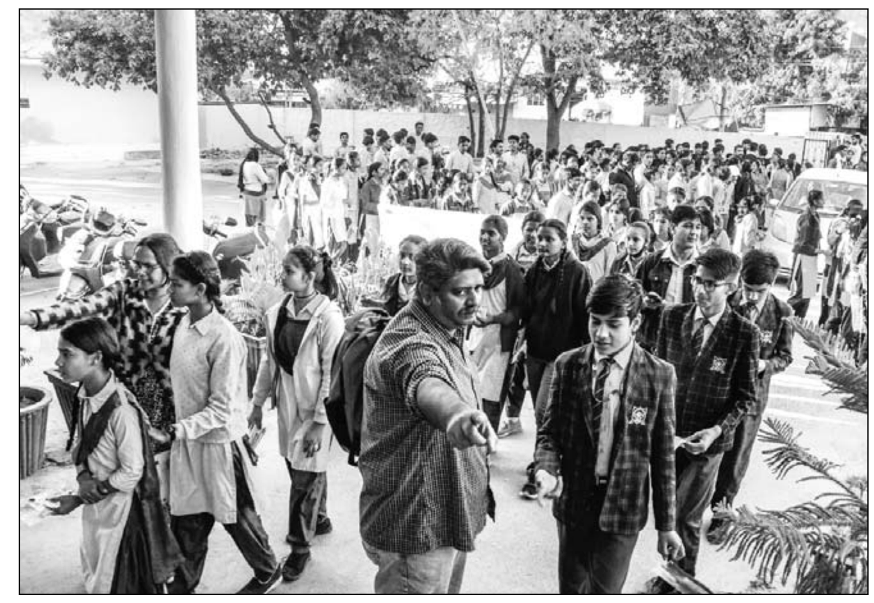

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की परीक्षाएं गुरुवार से शुरू हो गए। मालवीय नगर में सेक्टर 1 के गर्ल्स स्कूल में कक्षा 10 का एग्जाम देने जाते विद्यार्थी।

नागपुर में जल्द शुरू होगा 'पतंजलि मेगा फूड एंड हर्बल पार्क'

जयपुर। नागपुर के मिहान (नागपुर में मल्टी-मॉडल इंटरनेशनल कार्गो हब और एयरपोर्ट) क्षेत्र में पतंजलि मेगा फूड एंड हर्बल पार्क 9 मार्च को परिचालन शुरू करने के लिए तैयार है। मिहान में फूड प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करने हेतु भूमि पूजन का कार्य सितम्बर 2016 में किया गया था।

> लगभग 700 करोड़ किया जा चुका है निवेश, करीब 1500 करोड़ निवेश करने की योजना

नागपुर में स्थापित होने वाला पतंजलि का यह फूड्स एण्ड वेजीटेबल्स प्रोसेसिंग प्लांट है जिसमें सिटरस तथा ट्रॉपिकल फल व सब्जियों को प्रोसेस करके जूस, जूस कन्सेंट्रेट, पल्प, पेस्ट व प्यूरी का उत्पादन कर सकते हैं। जैसा की विदित है, नागपुर पूरे विश्व में ऑरेंज सिटी के नाम से विख्यात है, यहाँ सिटरस फ्रूट्स जैसे संतरा, कीनू, मौसम्मी, नींबू इत्यादि की बहुलता है। इसको दृष्टिगत रखते हुए पतंजलि ने सिटरस प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित किया है। इस सिटरस प्रोसेसिंग प्लांट में प्रतिदिन 800 टन फ्रूट प्रोसेस करके फ्रोजन जूस कन्सेंट्रेट बना सकते हैं। यह जूस 100 प्रतिशत प्राकृतिक है तथा इसमें किसी भी प्रकार के प्रिजर्वेटिव या शुगर का प्रयोग नहीं किया जाता।

इसके साथ-साथ ट्रापिकल फ्रूट्स का भी प्रसंस्करण किया जाता है जिसमें आँवला प्रतिदिन 600 टन, आम प्रतिदिन 400 टन, अमरूद प्रतिदिन 200 टन, पपीता प्रतिदिन 200 टन, सेब प्रतिदिन 200 टन, अनार प्रतिदिन 200 टन, स्ट्रॉबेरी प्रतिदिन 200 टन, प्लम प्रतिदिन 200 टन, नाशपाती प्रतिदिन 200 टन, टमाटर प्रतिदिन 400 टन, लौकी प्रतिदिन 400 टन, करेला प्रतिदिन 400 टन, गाजर 160 टन, एलोविरा 100 टन प्रतिदिन टन प्रोसेस करके वैश्विक विनिर्देश के अनुसार जूस, जूस कन्सेंट्रेट, पल्प, पेस्ट व प्यूरी का उत्पादन कर सकते हैं। फ्रूट से सीधे प्रोसेसिंग की इस प्रक्रिया को प्राइमरी प्रोसेसिंग कहते हैं।

इस प्लांट में अभी तक लगभग 700 करोड़ का निवेश किया जा चुका है। इस पूरी कार्य योजना में लगभग 1500 करोड़ निवेश की योजना है। इस प्लांट के स्थापित होने से यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर भी विकसित होगा।

दिया कुमारी को वीमन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवॉर्ड

जयपुर। पेसिफिक एशिया ट्रैवल राइटर्स एसोसिएशन ने राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किए गए सराहनीय कार्यों के लिए उप मुख्यमंत्री और पर्यटन मंत्री दीया कुमारी को वीमन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर, इंडिया के सम्मान से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह सम्मान आईटीबी बर्लिन, जर्मनी में सेशेल्स के पूर्व पर्यटन मंत्री डॉ. एलन सेंटएन्ज द्वारा दिया गया।

उप मुख्यमंत्री की ओर से पर्यटन विभाग के अधिकारी, अपर निदेशक आनंद त्रिपाठी, उप निदेशक पर्यटन उपेन्द्र सिंह शेखावत ने यह प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त किया।

गहलोत व डोटासरा विधानसभा के गौरवशाली इतिहास को कलंकित कर रहे हैं : राजेन्द्र राठौड़

जयपुर। विधानसभा में पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा कॉन्स्टीट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान के शुभारंभ को लेकर दिये गये बयान पर जोधपुर में आयोजित प्रेस वार्ता में प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि किसी भी सरकार के समय होने वाले निर्माण कार्य प्रदेश की जनता के टैक्स से होते हैं। गत सरकार में कॉन्स्टीट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान को संचालित करने वाली कार्यकारी संस्था का चयन नहीं हुआ था लेकिन अब विधानसभा अध्यक्ष द्वारा इस संस्था के चयन के बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सहित विधानसभा के सदस्यों को कॉन्स्टीट्यूशन क्लब के प्रवेश के समय आमंत्रित किया जाना पूरी तरह न्यायसंगत और विधिसम्मत है।

राठौड़ ने कहा कि जिस प्रकार घर में प्रवेश करते समय परिवार के सदस्यों को आमंत्रित किया जाता है उसी तरह कॉन्स्टीट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान का संचालन करने वाली संस्था के चयन के उपरांत क्लब के विधिवत कार्यशील होने के महत्वपूर्ण अवसर पर सदस्यों को आमंत्रित करना गलत कैसे हो सकता है? दुर्भाग्य है कि राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा राजस्थान विधानसभा के गौरवशाली इतिहास को कलंकित करने का काम कर रहे हैं और राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए विधानसभा अध्यक्ष का अपमान करने में जुटे हैं। राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस नेताओं द्वारा बार-बार विधानसभा अध्यक्ष को अपमानित करना ना केवल संसदीय परंपराओं को कमजोर करने का प्रयास है बल्कि उनकी संकीर्ण मानसिकता को भी दर्शाता है। कुछ दिनों पूर्व कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष द्वारा विधानसभा अध्यक्ष के प्रति निम्न स्तर के शब्दों का प्रयोग करना, निलंबित होने पर 7 दिन तक बेवजह गतिरोध बनाये रखना तथा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के माफी मांगने पर गतिरोध समाप्त होने के बाद भी सदन से लगातार अनुपस्थित रहना यह दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी में गहलोत बनाम पायलट गुट के अलावा अब नेता प्रतिपक्ष व कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष के नये गुट में अंतर्कलह प्रारंभ हो गई है।

श्रीजी का फाग उत्सव मनाया

जयपुर। श्रीजी का फाग उत्सव गुरुदेव गोस्वामी प्रेमकुमार महाराज, गोस्वामी हितेंद्र कुमार, गोस्वामी प्रियांश (छोटी सरकार श्रीधाम वृंदावन) के सानिध्य में मनाया गया। रसिक जन होली धमाल के पदों पर नृत्य कर बहुत आनंद लिया। फागोत्सव जवाहर सर्किल स्थित गोकुल वाटिका पर रविवार को फूलों की होली एवं भजन संध्या का आयोजन हुआ। आयोजक सुरेश टांक, राजेन्द्र, विष्णु टांक ने अतिथियों का दुपट्टा ओढ़ाकर और फूल बरसाकर सम्मान किया। विष्णु टांक ने बताया कि हर वर्ष फाग श्याम भजन संध्या का आयोजन किया जाता है। फूलों की होली खेली जाती है। राधाकृष्ण स्वरूप झांकी सजाई गई श्याम जी का फूलों की झांकी से श्रृंगार किया। श्याम रंग रसिया, फागण आयो रंग रसिया श्याम।

आर.यू.एच.एस. का कुलपति महाराष्ट्र के फार्मासिस्ट को बना दिया : बराला

'क्या राजस्थान का एक भी डॉक्टर इस पद के लाइक नहीं था?'

जयपुर। कांग्रेस विधायक शिखा मील बराला ने राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में गैर डॉक्टर को कुलपति बनाए जाने पर सवाल उठाए।

स्वास्थ्य विभाग की अनुदान मांगों पर बहस के दौरान शिखा मील बराला ने कहा कि आरयूएचएस में एक नई पर्ची के स्वास्थ्य विभाग के गलियारों में बड़े चर्चे हैं। आरयूएचएस वीसी पद पर महाराष्ट्र के रहने वाले फार्मासिस्ट को लगाया गया है, यह राजस्थान के सभी वरिष्ठ और योग्य अनुभवी डॉक्टर के पर एक सवालिया निशान है। ये वहीं डॉक्टर हैं, जिन्होंने अपने करियर में हजारों स्पेशलिस्ट तैयार कर दिए। क्या राजस्थान का एक भी डॉक्टर इस पद के लाइक नहीं था?

बराला ने कहा कि मेडिकल एजुकेशन की स्थिति बहुत चिंताजनक है। नए मेडिकल कॉलेजों में यू-ट्यूब से और बिना फैकल्टी पढ़ाई हो रही है और यह डॉक्टर हमारा इलाज करेंगे। इंडियन मेडिकल काउंसिल (आईएमसी) 8वीं-10वीं पास लोगों को फर्जी डिग्री देती है, ऐसे डॉक्टर फिर फील्ड में जाकर इलाज करेंगे तो मौतें होंगी, वो सरकार के खाते में लिखी जाएगी। राजस्थान में फिजियोथेरेपी काउंसिल नहीं है, इसकी स्थापना होनी चाहिए।

रंगाई-छपाई की 848 इकाइयों की संपत्ति कुर्क करने के आदेश पर रोक

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने सांगानेर की 848 रंगाई-छपाई इकाइयों से निकले अपशिष्टों के प्रबंधन के लिए बनाए सीईटीपी की निर्माण राशि व इससे जुड़ी करीब 96 करोड़ रुपए की वसूली के मामले में सांगानेर कपड़ा रंगाई छपाई एसोसिएशन के निदेशकों, पदाधिकारियों व सदस्यों के स्वामित्व वाली संपत्तियों को कुर्क करने के संबंध में कॉमर्शियल कोर्ट के गत 14 फरवरी के आदेश की क्रियान्विति पर अंतरिम रोक लगा दी है। जस्टिस अवनीश झिंगन व जस्टिस मनीष शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश गुरुवार को राज्य सरकार की अपील पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए।

अदालत ने कहा कि पहले याचिका की मेंटेनेबिलिटी पर सुनवाई की जाएगी। राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजेन्द्र प्रसाद ने कॉमर्शियल कोर्ट एक्ट, 2015 की धारा 13 के तहत अपील दायर कर कहा कि कॉमर्शियल कोर्ट का आदेश पूरी तरह से विधि के प्रावधानों के खिलाफ है। प्रार्थी फर्म अपने व्यावसायिक हितों के लिए कोर्ट के डिक्री आदेशों का क्रियान्वयन करवाना चाहता है। इसके जवाब में दावाकर्ता फर्म मैसर्स एडवेंट एंवायरकेयर टेक्नोलॉजीज ने कहा कि राज्य सरकार की अपील सुनवाई के लिए मेंटेनेबल नहीं है।

कैंसर जांच व जागरूकता अभियान

जयपुर। रघुकुल ट्रस्ट, भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल और कैंसर केयर की संयुक्त तत्वाधान में गुरुवार को जयसिंह पुरा रोड पर कैंसर जांच एवं जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। हवा महल क्षेत्र से एमएलए महाराज बालमुकुंद आचार्य की सानिध्य में, रोहित पब्लिक स्कूल के सहयोग से स्कूल परिसर में आयोजित इस शिविर में स्थानीय लोगों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। अभियान के उद्घाटन समारोह में पूर्व महापौर ज्योति खंडेलवाल ने कैंसर जांच के महत्व के बारे में बताया। इस मौके पर समाजसेवी व कैंसर विजेता साधना गर्ग ने जनता को प्रोत्साहित करके कहा की अर्ली डिटेक्शन कैंसर से बचने का मूल मंत्र है। कैंसर स्क्रीनिंग के माध्यम से कैंसर रोगी अपने आप को एवं अपने परिवार को आर्थिक, सामाजिक और मानसिक त्रासदी से बचा सकता है।

सहारा प्राइम सिटी के मामले में अभियुक्त की गिरफ्तारी के आदेश

जयपुर। राजस्थान राज्य उपभोक्ता आयोग द्वारा सहारा प्राइम सिटी के विरुद्ध अवमानना कार्रवाई को गंभीरता से लेते हुए अभियुक्तों की हर संभव गिरफ्तारी करने के आदेश दिए हैं। राज्य उपभोक्ता आयोग द्वारा दो दिनों में अलग-अलग कुल 67 अवमानना प्रकरणों की सुनवाई करते हुए पुलिस के विशेष बल द्वारा की गई कार्रवाई का अवलोकन किया।

पुलिस द्वारा बताया गया कि नोटिस तामील नहीं हो पा रहे है। आयोग के अध्यक्ष देवेंद्र कच्छवाहा, सदस्य न्यायिक निर्मल सिंह मेड़तवाल, सदस्य लियाकत अली ने आदेश दिया कि आयोग द्वारा लंबे समय से वारंट बार-बार जारी किए जा रहे हैं। विशेष पुलिस बल का गठन भी किया गया है। आयोग द्वारा अपने आदेश में कहा कि पुलिस रिपोर्ट के अवलोकन से ज्ञात हो रहा है कि वारंटी जानबूझकर प्रकरणों में पूर्व में जारी जमानती वारंट की तरह गिरफ्तारी वारंट की भी तमिल से बच रहे हैं, और निकट भविष्य में वारंटी की तमिल सामान्य क्रम में होने की संभावना नहीं है। अतः प्रकरण के शेष अप्रार्थी, अभियुक्त के विरुद्ध वारंट पुनः जारी कर विशेष पुलिस दल को सुपुर्द किए जाए और गिरफ्तारी वारंट पर पूर्व की तरह शर्त लिखी जावे।

राष्ट्रीय लोक अदालत 8 को

जयपुर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में 8 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।

यह लोक अदालत राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर एवं जयपुर पीठ सहित प्रदेश के सभी अधीनस्थ न्यायालयों, राजस्व न्यायालयों, उपभोक्ता आयोगों एवं अन्य प्रशासनिक प्राधिकरणों में आयोजित होगी। राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में इस लोक अदालत का शुभारंभ राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष व उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस श्री चंद्रशेखर तथा राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ में राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष व उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस इंद्रजीत सिंह की अध्यक्षता में प्रातः 10 बजे किया जाएगा।

राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद लागू होगा एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट : पटेल

जयपुर। विधि एवं विधिक कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने गुरुवार को विधानसभा में कहा कि राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाएगा। पटेल प्रश्नकाल में पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार द्वारा राज्य में अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल विधानसभा में प्रस्तुत किया गया था। इसे 15वीं विधानसभा के अष्टम सत्र में 21 मार्च 2023 को विधानसभा द्वारा पारित किया गया। उन्होंने बताया कि इस बिल पर राष्ट्रपति की स्वीकृति अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

> विधायक अमीन कागजी के प्रश्न पर विधि मंत्री जोगाराम पटेल ने जवाब दिया

इससे पहले विधायक अमीन कागजी के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के 31 जिला एवं सेशन न्यायालय परिसरों की सुरक्षा व्यवस्था की गई है। इनमें वर्तमान में 33 हैड कांस्टेबल तथा 131 कांस्टेबल सुरक्षा गार्ड उपलब्ध हैं।

भ्रष्टाचार उन्मूलन की दिशा में सशक्त अनुसंधान एवं प्रभावी अभियोजन महत्वपूर्ण : डॉ. मेहरड़ा

जयपुर। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान द्वारा गुरुवार को जयपुर स्थित राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में "इन्वेस्टीगेशन ऑफ डी ए केसेस : ए कंप्रेहेंसिव एप्रोच इन दी लाइट ऑफ न्यू क्रिमिनल लॉज " विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।

कार्यशाला का उद्घाटन मुख्य अतिथि महानिदेशक, एसीबी डॉ. रवि प्रकाश मेहरड़ा और विशिष्ट अतिथि डी.सी. जैन, सेवानिवृत्त डीजी द्वारा किया गया। महानिदेशक एसीबी मेहरड़ा ने अपने संबोधन में कहा कि इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य आय से अधिक सम्पति मामलों पर विस्तार से चर्चा कर डी ए केसेस की जांच को नए आपराधिक कानूनों के तहत अधिक प्रभावी बनाना और अभियोजन प्रक्रिया को मजबूत करना है। महानिदेशक ने कहा कि इस तरह की कार्यशालाएं ब्यूरो के अधिकारियों को एक प्लेटफार्म पर नये क़ानून पर एक साथ चर्चा करने से प्रभावी ज्ञानवर्धन का अवसर प्रदान करती है। उन्होंने कहा कि इससे भविष्य में आपसी समन्वय की भावना के साथ मजबूत अनुसंधान करने में भी सहायता मिलेगी। उन्होंने इस कार्यशाला को अनुसंधान अधिकारियों और अभियोजन अधिकारियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि इस कार्यशाला से राज्य सरकार की भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस नीति को प्रभावी रूप से लागू करने में सहायता मिलेगी।

इस अवसर पर मुख्य वक्ता: डी.सी. जैन, सेवानिवृत्त डीजी ने पहले सत्र में "अंडरस्टैंडिंग दी न्यूसेन्स इन्वॉल्वड इन दी इन्वेस्टीगेशन ऑफ़ डी ए केसेस" विषय पर सम्बोधन में डीए मामलों की जांच के जटिल पहलुओं को समझने पर चर्चा की गई। डी.सी. जैन ने संपत्ति की जांच, वित्तीय विश्लेषण, और सबूतों की सत्यता सुनिश्चित करने के विभिन्न पहलुओं पर गहराई से प्रकाश डाला।

इस अवसर पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के कालूराम रावत, उप महानिरीक्षक प्रथम, राजेश सिंह, उप महानिरीक्षक तृतीय, अनिल कयाल, उप महानिरीक्षक चतुर्थ एवं शिवराज सिंह, उप महानिरीक्षक कोटा रेंज, पुलिस अधीक्षक प्यारेलाल शिवरान, वित्तीय सलाहकार सांवरमल और ए सी बी की सभी यूनिट्स में पदस्थापित अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तथा ब्यूरो के अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

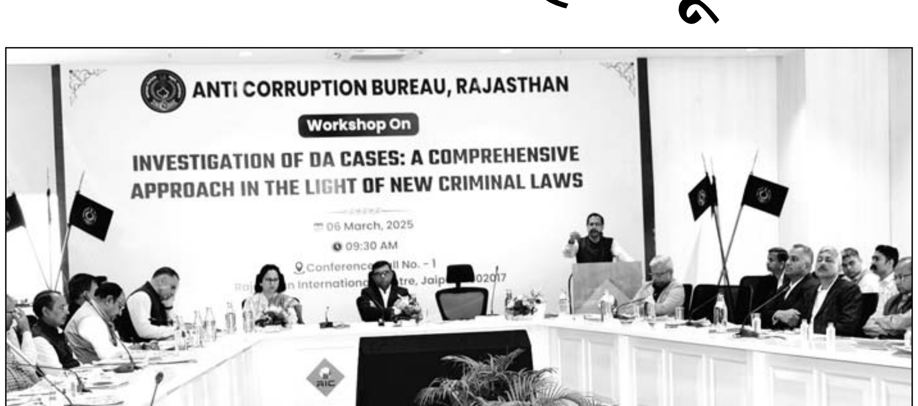

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ओर से गुरुवार को जयपुर स्थित राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में "इन्वेस्टीगेशन ऑफ डी ए केसेस : ए कंप्रेहेंसिव एप्रोच इन दी लाइट ऑफ न्यू क्रिमिनल लॉज" विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया।

कांस्टीट्यूशन क्लब के उद्घाटन का कांग्रेस बहिष्कार करेगी

जयपुर। कांस्टीट्यूशन क्लब को लेकर प्रदेश में सियासी पारा गरम हो गया है। कांग्रेस ने 8 मार्च को होने वाले उद्घाटन का बहिष्कार का ऐलान कर दिया। कांग्रेस ने कहा कि जिसका उद्घाटन हो चुका, उसका फिर से उद्घाटन क्यों? हम बहिष्कार करते हैं।

कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि हमारी सरकार ने कांस्टीट्यूशन क्लब न केवल बना दिया था, बल्कि उसकी उद्घाटन भी कर दिया था। बावजूद इसके, अब इसका फिर से उद्घाटन किया जा रहा है। 8 मार्च को होने वाले उद्घाटन समारोह में कांग्रेस शामिल नहीं होगी। हम इस समारोह का बहिष्कार करते हैं। जूली ने कहा कि उद्घाटन हो चुका है, शुभारंभ के नाम पर वापस इसका उद्घाटन करना चाह रहे हैं। यह गलत परंपरा है। इस गलत परंपरा का हमारी पूरी पार्टी, पूरा विधायक दल इसका बहिष्कार करेगा। इस प्रकार से गलत परंपरा में विपक्ष शामिल नहीं होगा। जूली ने कहा कि कांस्टीट्यूशन क्लब में पट्टिका लगी हुई है। क्लब का उद्घाटन पहले हो चुका है। इस पर पुनर्विचार किया जाए।

> कांग्रेस बोली, "दोबारा उद्घाटन क्यों? हम बहिष्कार करते हैं"

भाजपा विधायक गोपाल शर्मा ने कहा कि कांग्रेस ने सिर्फ पट्टियां लगाने का काम किया। विधायक आवास में डेढ़ साल नहीं हुआ, दरारें आ गई, टाइलें उखड़ गई, छत से पानी टपकने लग गया। कांग्रेस ने ऐसे भ्रष्टाचार के नमूने जगह-जगह खड़े कर दिए। कांग्रेस ने सिर्फ सिलापट्टी का लगाना और लगाते जाने का ही काम किया। इसलिए, कांग्रेस के आरोप यह सब फिजूल की बातें हैं।

मादक पदार्थों की तस्करी के मामले में की जायेगी सख्त कार्रवाई : बेढ़म

जयपुर। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने गुरुवार को विधानसभा में आश्वस्त करते हुए कहा कि प्रदेश में मादक पदार्थों की तस्करी एवं बिक्री रोकने के लिए राज्य सरकार सजग है और अपराधियों के साथ पुलिस की मिलीभगत एवं तस्करी में लिप्त की शिकायत पर सख्त कार्रवाई की जायेगी। बेढ़म प्रश्नकाल में पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे।

उन्होंने नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के पूरक प्रश्न 'क्या मादक पदार्थ तस्करी मामलों में पुलिस की गठजोड की शिकायत प्राप्त हुई है और तस्करी रोकने की कोई कार्ययोजना है' पर कहा कि मिलीभगत की कोई शिकायत अब तक प्राप्त नहीं हुई है। उन्होंने सदन को आश्वस्त किया कि ऐसी कोई भी शिकायत आने पर कठोर कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में मादक पदार्थों की अवैध बिक्री और तस्करी रोकने के लिए सजगता से कार्रवाई की जा रही है।